

199

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० 819 / 2011 / टी०सी० 17(120) / XXVII(8) / 2009

दिनांक: देहरादून :: 25 जुलाई, 2011

अधिसूचना

चूंकि कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है;

अतः राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 4.क की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके दिनांक 29-04-2011 से 31-05-2011 में प्रस्तावित सुख-साधन कर की पूर्ण रूप से भुगतान पर छूट देने की शक्ति करनिर्धारण अधिकारी को निम्नलिखित प्रतिबन्धों पर प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. कर निर्धारण अधिकारी करदाता की पुस्तकों की जाँच कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि दिनांक 29-04-2011 से 31-05-2011 की अवधि में नयी कर दर से सुख-साधन कर की वसूली नहीं की गयी है।
2. उक्त जाँच के उपरान्त कर निर्धारण अधिकारी अपने क्षेत्र के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
3. यदि करदाता द्वारा दिनांक 29-04-2011 से 31-05-2011 की अवधि के मध्य नयी दर से सुख-साधन कर की वसूली की गयी है तो उसे करदाता को वापस नहीं किया जायेगा और उसे नियमानुसार कोषागार में जमा किया जायेगा।

(आलोक कुमार (जैन))

प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० 819 / 2011 / टी०सी० 17(120) / XXVII(8) / 2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की, जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाइल हेतु / एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(राधा शर्मा)

सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification NO. /2011 / T.C. 17 (120)/ XXVII(8)/2009 dated July, 2011 for general information.

Uttarakhand Shasan

VITTA ANUBHAG-8

NO. /2011 /T.C. 17 (120)/ XXVII(8)/2009

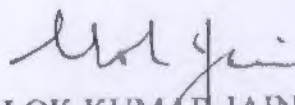
Dehradun :: Dated: : July, 2011

Notification

WHEREAS, it is necessary and expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4.A of the Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975(as applicable to the State of Uttarakhand) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904(U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow to give the powers to the assessing officer to exempt the full payment of proposed Luxury Tax during the period from 29-04-2011 to 31-05-2011 with the following conditions-

1. The assessing officer shall, on examination of accounts books of assessee, insure that the Luxury Tax has not been realised at the new rates during the period from 29-04-2011 to 31-05-2011.
2. After above examination, the assessing officer shall seek the approval of the Joint Commissioner (Executive) Commercial tax of his area.
3. If the luxury tax at the new rates has been realised by the assessee during the period from 29-04-2011 to 31-05-2011 it shall not be refunded to the assessee and shall be deposited in the treasury as per rules.


(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.

